Shodh ManthanVol. XVII Special Issue Jan.2026 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X, Impact Factor 8.889 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17SI01.01

भारत के सर्वांगीण विकास में डिजिटलीकरण की भूमिकाः एक समीक्षात्मक अध्ययन

01

प्रो. (डॉ.) कमल सिंह
प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद (उ.प्र.)

सारांश

वर्तमान युग को यदि डिजिटलीकरण का युग कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं, वित्तीय लेनदेन, कृषि एवं पुलिसिंग जैसे लगभग समस्त क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों, ई–लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल संसाधनों से देश के छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श के माध्यम से ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जा रही हैं। यूपीआई, पेटीएम और फोनपे जैसे विभिन्न प्रकार के ऐप्स ने डिजिटल भुगतान को आसान और बहुत तेज बना दिया है जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। सरकारी सेवाओं में आधार, ई–गवर्नेंस और डीबीटी जैसी पहलों के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम हुआ है तथा पारदर्शिता भी बढ़ी है। आपराधिक और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटलीकरण से पूरे भारत में पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिली है, जिससे भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने प्रस्तावना, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान, भारत के गाँव–गाँव में झलक रही डिजिटल इण्डिया की सफलता, भारत में ग्राम पंचायतों में डिजिटलीकरण की भूमिका, वैश्विक पटल पर यूपीआई की भूमिका, डिजिटलीकरण का भारत की जीडीपी में योगदान का अध्ययन किया है तथा साथ ही साथ हमने रोजगार सष्जन एवं उद्यमिता विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका, कुशल एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था में डिजिटलीकरण की भूमिका, भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण की भूमिका तथा भारत में डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ और उनका समाधान एवं निष्कर्ष का अध्ययन किया है।

मुख्य शब्द

डिजिटलीकरण, आधार, डिजिटल इण्डिया, यूपीआई, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया, डिजिटल पॉल्यूशन, सर्वांगीण विकास।

प्रस्तावना

भारत में डिजिटलीकरण का इतिहास डॉट कॉम बबल के समय से हुआ, जब इंटरनेट कंपनियों का मूल्य बढ़ा। भारत में वर्ष 2006 में ई–गवर्नेंस की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2015 में भारत में डिजिटल इण्डिया पहल ने एक क्रान्ति ला दी। डिजिटल इण्डिया पहल ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त एवं मजबूत समाज का निर्माण करने एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा, जिसने शासन, सेवाओं और समाज के अन्य पहलुओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। वर्ष 2000 के दशक की शुरूआत में डॉट कॉम बबल के बाद इंटरनेट और आईटी कम्पनियों में निवेश बढ़ा, जिसने भारतीय आईटी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। वर्ष 2006 में ई–गवर्नेंस पहल के द्वारा सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की थीं, हालांकि शुरूआत में ये योजनाएँ उतनी सफल नहीं रही थीं। भारत में 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इण्डिया अभियान की शुरूआत की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, ग्रामीण क्षेत्रों को हाईस्पीड़ इंटरनेट से जोड़ना, डिजिटल साक्षरता में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देना आदि था। आधार ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जैम (JAM) यानि जनधन, आधार और मोबाइल के एकीकरण ने भारत के लाखों लोगों को औपचारिक रूप से पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। वर्ष 2016 में यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया। भारत नेट ने देश की ग्राम पंचायतों तक ब्रांडबैंड पहुँचाया। ई–संजीवनी के द्वारा टेलीमेडिसिन प्लेटफार्म ने भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं। ई–नाम और पीएम किसान जैसी पहलों ने भारत में कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। डिजिटलीकरण में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके मुख्य कारणों में 5जी

तकनीक, हाईस्पीड ब्रॉडबैंड और किफायती डेटा है। डिजिलॉकर सरकारी दस्ताबेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत एवं सुरक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्ष 2006 से भारत में जो डिजिटलीकरण का दौर शुरू हुआ है उसने भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का काम किया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान– भारत में दुनिया का सबसे बडा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 7.35 करोड़ से अधिक ग्रामीण लोग पंजीकृत हो चुके हैं जिसमें से 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन से कम्प्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा प्राप्त कर ग्रामीण लोग ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों के लिए स्पष्ट नीतियाँ बनायी हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एआई मिशन और इण्डिया एक्ट जैसी नीतियाँ काबिले तारीफ हैं। डिजिटल प्रगति के लिए अक्सर एस्तोनिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का नाम लिया जाता है लेकिन वर्तमान में भारत की प्रगति यह है कि उसने इतनी विशाल जनसंख्या को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया है। हमारी ऑनलाइन वित्तीय भुगतान प्रणालियाँ तो इस समय विश्व में अब्बल हैं। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधाएँ देना, सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन पहुँचाना तथा देश को एक ज्ञान आधारित समाज बनाना रहा है ने अब तक काफी अच्छे परिणाम दिखाए हैं। वर्तमान डिजिटल तकनीक ने जिस तरह से भारत के आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है वह किसी क्रान्ति से कम नहीं है। इस अभियान के तहत हम प्रत्येक गाँव–गाँव तक इंटरनेट तथा दूसरे संचार के साधनों को पहुँचाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। वर्ष 2015 में जब डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत की गयी थी तब देश में सिर्फ 19% लोग इंटरनेट से जुड़े थे और मात्र 15% लोगों के पास मोबाइल फोन थे। आज भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी इंटरनेट से जुड़ी है और लगभग 80% लोग मोबाइल फोन रखते हैं। वर्तमान समय में देश को आत्मनिर्भर, समावेशी और ज्ञान आधारित समाज में तब्दील करने की हमारी जद्दोजहद में डिजिटल इण्डिया की भूमिका अहम है और अहम बनी रहेगी। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी में आईटी और आईटी आधारित सेवाओं की हिस्सेदारी 10% तक पहुँचने का अनुमान है जो वर्ष 1998 में मात्र 1.2% थी।

भारत के गाँव–गाँव में झलक रही डिजिटल इण्डिया की सफलता– कभी भारत में गाँव का मतलब होता था मिट्टी के घर, लालटेन की रोशनी, चिकित्सा सेवाओं का अभाव और शहरों पर जिंदगी की निर्भरता। लेकिन वर्तमान भारत बदल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गयी डिजिटल इंडिया मुहिम ने भारत के गाँव–गाँव तक भी विकास की रोशनी को पहुँचा दिया है। आज देश के 6 लाख से अधिक गाँवों में से अधिकतर को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अब तक लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में हाई–स्पीड इंटरनेट पहुँचा है। ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवान अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसान मोबाइल मे मंडी भाव देख रहे हैं और महिलाएँ डिजिटल भुगतान में आत्मनिर्भर बन रही हैं। डिजिटल इंडिया ने शहरों के साथ–साथ गाँवों में भी तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित किया है, खासकर स्टार्टअप्स और शोध क्षेत्र में। ब्लाक–चेन, कृतिम बुद्विमता और आईओटी जैसे क्षेत्रों का शोध भी आज गाँव के लिए अनजान नहीं रहा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार अकादमिक संस्थानों और आईटी उद्योग के साथ मिलकर ग्रामीण भारत की समस्याओं के समाधान पर जोर दे रही हैं। डिजिटल कृषि मंच आ गये हैं, टेलीमेडिसिन और ई–गवर्नेंस टूल्स जैसे समाधान विकसित किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार के उमंग ऐप से ग्रामीणों को 1200 से ज्यादा सरकारी सेवाएँ मोबाइल फोन पर ही मिल रही हैं। आज भारत में इंटरनेट पर लगभग 60% से अधिक कंटेंट क्षेत्रीय भषाओं में हैं जिसका उपयोग करते हुए भारतीय भाषाओं में काम करने वाले ऐप्स और प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। ऐसे डिजिटल टूल्स गैर–अंग्रेजी भाषी राज्यों के लिए भी सुलभ हो गये हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और पीएम विद्या जैसी योजनाओं से देश के विशेषकर ग्रामीण भारत के लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिला है। वर्तमान समय में भारत में इंटरनेट के प्रयोग में लैंगिक असमानता भी घट रही है क्योंकि आज इंटरनेट का प्रयोग करने वालों में 53% पुरूष और 47% महिलाएँ हैं। आज भारत में सस्ते इंटरनेट और मोबाइल की वजह से लाखों लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेट बना रहे हैं।

भारत की ग्राम पंचायतों में डिजिटलीकरण की भूमिका– भारत में ग्राम पंचायतों को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए डिजिटलीकरण किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाना, कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करना और ग्रामीण शासन को मजबूत करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रान्ति पर आधारित ई–ग्रामस्वराज प्रभावी विकेन्द्रीकरण, सार्वजनिक सेवा के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले धन की जवाबदेही के संवर्धन, दुर्लभ संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा स्थानीय शासन की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के कई प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करता है। संचार प्रौद्योगिकी तेजी से पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक कार्यकुशलता की बुनियाद बनती जा रही है। भारत में वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 2.56 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड की गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में अपलोड की गयी जीपीडीपी संख्या मात्र 2.43 लाख थी। ग्राम पंचायतों की अपलोड की गयी विकास योजनाओं तथा निर्धारित और पूर्ण गतिविधियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है–

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17SI01.01

तालिका– 1

ग्राम पंचायत विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्यवार ब्यौरा (05.02.2023 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित प्रदेश	पारंपरिक स्थानीय निकायों समेत कुल ग्राम पंचायतें	अपलोड की गई जीपीडीपी	निर्धारित गतिविधियाँ	पूर्ण गतिविधियाँ
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	70	5701	0
2.	आंध्र प्रदेश	13225	13323	153744	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	2108	1955	11029	0
4.	असम	2663	2191	22491	0
5.	बिहार	8174	8067	426351	74
6.	छत्तीसगढ़	11659	11646	239999	26
7.	गोवा	191	190	4648	0
8.	गुजरात	14365	14200	140899	0
9.	हरियाणा	6229	6225	42132	63
10.	हिमाचल प्रदेश	3615	3602	42706	6
11.	जम्मू कश्मीर	4291	4289	67439	0
12.	झारखंड	4345	4333	158982	4
13.	कर्नाटक	5958	5789	193892	14
14.	केरल	941	941	23696	7
15.	लद्दाख	193	193	4059	0
16.	लक्षद्वीप	10	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	23032	22884	513475	79
18.	महाराष्ट्र	27897	27828	503456	12
19.	मणिपुर	3812	758	28782	0
20	मेघालय	6811	0	0	0
21.	मिजोरम	834	763	2324	0
22.	नागालैंड	1292	0	0	0
23.	ओडिशा	6794	6749	186740	294
24.	पंजाब	13234	13220	56114	0
25.	राजस्थान	11303	11302	559112	239
26.	सिक्किम	198	179	3977	0
27.	तमिलनाडु	12525	12386	63140	0
28.	तेलंगाना	12769	12756	171153	30
29.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38	38	753	0
30.	त्रिपुरा	1178	1176	106039	1
31.	उत्तराखंड	7814	7783	91818	5
32.	उत्तर प्रदेश	58184	58040	2795415	98
33.	पश्चिम बंगाल	3339	3052	275798	30
	कुल	**2,69,191**	**2,55,928**	**68,95,864**	**982**

स्रोत : राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 719 का दिनांक 08.02.2023 को दिया गया उत्तर।

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2022–23 तक के जो राज्यवार आँकड़े दिये गये हैं उसमें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के अन्तर्गत जो गतिविधियाँ निर्धारित की गयी हैं उनमें पूर्ण होने वाली गतिविधियों की संख्या बहुत कम है। 33 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में निर्धारित गतिविधियों में से पूर्ण होने वाली गतिविधियों में सबसे अच्छी स्थिति ओडिसा और राज्स्थान की है।

वैश्विक पटल पर यूपीआई की भूमिका– यूपीआई यानि–यूनिफाइड पेमेंटस सिस्टम। यूपीआई की शुरूआत दिल्ली से हुई। सबसे पहले एक ग्राहक ने अपने मोबाइल पर अँगुली फेरी और चाट वाले के खोमचे पर रखा साउंड बाक्स बोल उठा। पलक झपकते ही उसके बैंक खाते में 20 रूपये पहुँच चुके थे। खुले पैसे की कोई झिकझिक नहीं हुई। यूपीआई ने देश में पैसे भेजने तथा प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। यह बैंकों के खातों को एक ही मोबाईल ऐप में जोड देता है। यूपीआई की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति और सहजता है। वर्तमान समय में भारत में प्रत्येक महीने 20 अरब से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं। आईएमएफ ने जून 2025 में जारी किये गये एक वित्त प्रौद्योगिकी नोट में 'बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान अंतरसंचालनीयता का महत्व' शीर्षक में उसकी सराहना की और कहा कि यूपीआई ने भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। यह पूरी वैश्विक दुनिया के लिए एक मिशाल है। भारत में यूपीआई की शुरूआत किसी ऐप से नहीं, बल्कि एक विचार से हुई है। भारत के नीति निर्माताओं ने यूपीआई को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना नाम दिया है। यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना वास्तव में निम्न सुधारों की तिकडी हैः पहली जनधन योजना जिसके तहत भारत में सभी बैंकों में भारतीयों द्वारा करोड़ों बैंक खाते खोले गये। आधार जिसने भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बायोमैट्रिक पहचान दी है। भारत में बहुत सस्ता मोबाइल डाटा जिसने इंटरनेट को आम नागरिकों तक पहुँचाया है। यूपीआई से अब कुछ प्रमुख श्रेणियों के लिए प्रतिदिन 10 लाख रूपये तक के व्यापारिक लेनदेन की अनुमति दे दी गयी है, जबकि सभी के लिए प्रतिदन की सीमा 1 लाख रूपये तक है। वर्तमान समय में यूपीआई अब वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है क्योंकि भारत के अतिरिक्त विश्व के सात प्रमुख देशों क्रमशः भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन हो रहा है। यूपीआई आज एक भुगतान के माध्यम से कहीं बढ़कर है क्योंकि इसने न केवल भारत में बल्कि विश्व के कुछ प्रमुख देशों में भुगतान की प्रक्रिया को बहुत सरल, सुगम एवं आम जनता की पहुँच तक कर दिया है। नकदी से लेकर क्लिक करने तक डिजिटल रथ पर सवार होकर भारत विश्व मंच पर पहुँच रहा है, जिस पर विश्व भर की नजर है।

डिजिटलीकरण का भारत की जीडीपी में योगदान– पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि डिजिटलीकरण का भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह योगदान डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, डिजिटल भुगतान प्रणालियों में वृद्धि, बढ़ी हुई इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं ई–गवर्नेंस के विस्तार के कारण संभव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में डिजिटलीकरण का भारत की जीडीपी में जो योगदान 11.74% या 31.64 लाख करोड़ रूपये था उसका वर्ष 2029–30 तक 20% तक पहुँचने का अनुमान है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्थता राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में दो गुनी तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई ने कमाल कर दिया है। अक्टूबर– 2025 में भारत में 20.7 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए, जिनमें 27 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान हुआ। ताजा आँकड़ों के अनुसार त्यौहारी सीजन में भारत में यूपीआई ने केवल 18 अक्टूबर, 2025 को अकेले एक लाख करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया। करीब 67.5 करोड़ लेन–देन प्रतिदिन भारत में हो रहे हैं यानि विश्व के लगभग आधे डिजिटल पेमेंट केवल भारत में हो रहे हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में उसकी स्थानीय भाषा के अनुसार डिजिटल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं तथा आईटी क्षेत्र में लगभग 5.4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है जिससे यह भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बन गया है।

रोजगार सृजन एवं उद्यमिता विकास में डिजिटलीकरण की भूमिका– भारत एक विशाल देश है यह जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। भारत में बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में डिजिटलीकरण ने रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटलीकरण देश में रोजगार के अवसर पैदा करता है, उत्पादकता बढ़ाता है, लागत कम करता है, और उद्यमियों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद करता है। वर्तमान समय में डिजिटलीकरण ने ई–कॉमर्स और आईटी क्षेत्रों में नौकरियाँ पैदा की हैं, देश के पारंपरिक क्षेत्रों में डिजिटल दक्षता बढ़ाई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया है। डिजिटल बुनियादी ढ़ाँचा और कौशल विकास कार्यक्रम देश में नये उद्यमों को बढावा दे रहे हैं। डिजिटलीकरण ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है। जिससे कृषि और पारंपरिक लघु उद्योगों से परे आर्थिक विकास हुआ है। भारत में डिजिटल उपकरण और प्लेटफार्म उद्यमियों को वित्तीय, तकनीक और मार्गदर्शन संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं जिससे नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्यमियों को भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद करते हैं। भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक डिजिटल कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं जो उद्यमियों को प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान, आईटी मीड़िया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की माँग बढ़ रही है।

कुशल एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था में डिजिटलीकरण की भूमिका– भारत में कुशल एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था को चलाने में डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभरा है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसी अनेकों पहलों ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से पहुँचाने, नौकरशाही को कम करने और जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटलीकरण ने नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी, नीतियों और सेवाओं तक पहुँच को बहुत आसान बना दिया है जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है। राशन वितरण, मनरेगा भुगतान एवं डीबीटी में डिजिटलीकरण के कारण भ्रष्टाचार में कमी आई है। ऑनलाइन पोर्टल और प्लेटफार्म ने भारत के नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रक करने में सक्षम बनाया है, जिससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। ई–गवर्नेंस प्लेटफार्म ने पासपोर्ट, पैनकार्ड, जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र, श्रमकार्ड, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि के वितरण को बहुत तेज, सुविधानजक और कुशल बना दिया है। मोबाइल फोन के प्रयोग से अनेक सेवाओं का

सपना साकार हुआ है। सरकारी प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण ने लालफीताशाही और कागजी कार्रवाही को कम किया है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि डिजिटलीकरण ने भारत में सरकार और जनता के बीच की खाई को काफी हद तक पाटा है जिससे एक ऐसी शासन प्रणाली तैयार हुई है जो अधिक नागरिक–केंद्रित एवं सुलभ और पारदर्शी है।

भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण की भूमिका– भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि डिजिटलीकरण से स्वास्थ्य सेवा की लागत कम होती है तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ती है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से डाक्टर दूर बैठे मरीजों को भी परामर्ष दे सकते हैं, जिससे भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार हुआ है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड और डेटा एनाटिक्स से बीमारियों के पैटर्न को समझने और उनकी रोकथाम के लिए बेहतर रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिल रही है। डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप जैसे साहसिक सुधारों ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत बनाया है। मोबाइल एप्लिकेशन ने वर्तमान समय में आँगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को वास्तविक समय में विकास चार्ट, एनीमिया की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर रखने में सक्षम बनाया है। डिजिटलीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मिलता है जहाँ ओपीडी बुकिंग ने दिल्ली के लाखों मरीजों की कतारों और प्रतीक्षा समय को कम किया है। वर्तमान समय में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ाँचे और नीतियों के प्रति भारत सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण एक अधिक कुशल और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आकार दे रहा है।

भारत में डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ और उनका समाधान– भारत में डिजिटलीकरण की कुछ मुख्य चुनौतियाँ निम्न हैं–

1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय हाईस्पीड इंटरनेट तक पहुँच की कमीं है तथा जिसमें बिजली की आपूर्ति भी एक कारक है।
2. डिजिटल उपयोग में अत्यधिक वृद्धि के साथ साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों का खतरा बढ़ रहा है।
3. आजकल भारत में अधिकतर लोग कई–कई घण्टे रील पर समय व्यतीत कर रहे हैं। यह एक तरह का डिजिटल पॉल्यूशन है।
4. एक बार अगर कोई व्यक्ति किसी एप को अपने फोन में इंस्टाल करता है या लॉगिन कर लेता है तो उसका पूरा व्यक्तिगत डेटा साइबर ठगों के पास पहुँच जाता है।
5. साइबर ठग उस व्यक्तिगत डेटा का गलत प्रयोग कर सकते हैं अर्थात वह उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट कर बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं।
6. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुँच और उपयोग में महत्वपूर्ण अन्तर आज भी मौजूद है।
7. ई–गवर्नेंस प्रणालियों को बनाये रखने और अपडेट करने के लिए कुशल कर्मियों की कमीं हैं, आदि।

डिजिटलीकरण की उपरोक्त चुनौतियों का भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ाँचे का विकास करके, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए निवेश बढ़ाकर, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके, आक्रामक साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाकर तथा जागरूकता बढ़ाकर, सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके एवं सभी हितधारकों के बीच एक मजबूत और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देकर उनका समाधान किया जा सकता है।

निष्कर्ष– भारत में डिजिटलीकरण ने अर्थव्यवस्था को काफी हद तक गति प्रदान की है। सरकारी सेवाओं को जनता के लिए काफी हद तक सुलभ बनाया है। भारत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार में कमीं तथा पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान यूपीआई जैसे साधन ने नवाचारों को जन्म दिया है। वर्तमान में भारत के ग्रामीण इलाकों में डिजिटलीकरण ने सभी का जीवन आसान बना दिया है, क्योंकि आज किसान मंडी भाव भी मोबाइल पर देख रहे हैं और महिलाएँ यूपीआई से भुगतान कर रही हैं। डिजिटलीकरण ने भारत की ग्राम पंचायतों को सीधे भारत नेट के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है जिससे ई–ग्राम पंचायतें क्षेत्र का विकास कर रही हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारत में डिजिटलीकरण ने शासन, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया है। वर्तमान समय में डिजिटलीकरण के कारण ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा सकती है कि भारत जल्दी ही आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और वर्ष 2047 के विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर कदम बढायेगा।

सन्दर्भ

1. कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक पत्रिका, अक्टूबर 2025, सितम्बर 2025, अप्रैल 2023।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, वी0के0 पुरी एवं एस0के0 मिश्र।
3. अमर उजाला 10 नवम्बर, 2025, 13 नवम्बर, 2025 मुरादाबाद संस्करण।
4. दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक अखबार।
5. Amoghhvarta, https://wwwamoghvarta.com
6. Vikaspedia, https://egovernance.vikaspedia.in
7. Perform India, https//www.performindia.com